साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

भोपाल, सोमवार 28 नवंबर-4 दिसंबर , 2022, वर्ष-8, अंक-34

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

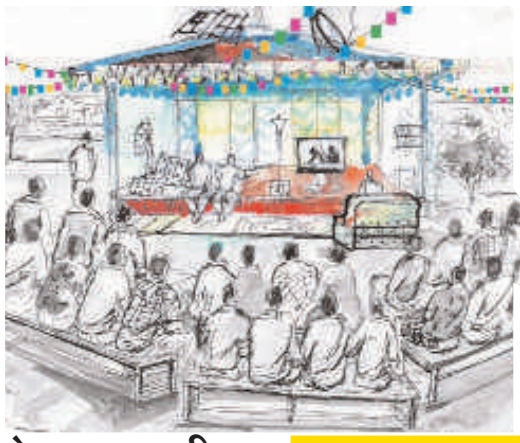

चौपाल से भोपाल तक

वनोपज बेच सकेंगे आदिवासी विवाद सुलझाने, शराब बिक्री की परमिशन ग्रामसभा को

टंट्या भील की जन्मस्थली पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बोले

अब गांव की चौपाल से चलेगी सरकार

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने बुधवार को खंडवा जिले के पंधाना नगर में पेसा एक्ट जागरुकता और ग्रामसभा कार्यक्रम को लेकर जनसभा की। शिवराज यहां पर टंट्या भील की जन्मस्थली पर जनजाति गौरव यात्रा में शामिल होने आए थे। मुख्यमंत्री ने कहा, अब प्रदेश की सरकार भोपाल से नहीं बल्कि गांव की चौपाल से चलेगी। अक्ल का चक्का नेता-अफसर के पास ही नहीं गरीब के पास भी है। इसलिए अब वह वनोपज, तेंदुपत्ता खुद बेच सकेंगा। यहां तक ग्रामसभा में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी ले सकेंगे।

पंधाना स्थित कृषि उपज मंडी में जनसभा को संबोधित करते हुए शिवराज ने कहा कि, अब अनुसूचित गांवों में जनता के बीच पटवारी और वन विभाग के अफसर जाएंगे। हर साल खसरा नकल ग्रामीणों के सामने रखकर बताएंगे कि यह जमीन किसकी है। ताकि ऐसा न हो कि धन्ना की जमीन पन्ना के नाम हो गई हो और धन्ना को मालूम ही न हो। अब सरकारी निर्माण कामों में आदिवासी क्षेत्रों की जमीन उनकी बगैर अनुमति के नहीं ली जाएगी। मालिक के अलावा ग्रामसभा की अनुमति भी ली जाएगी, तभी जमीन का अधिग्रहण हो सकेगा। कोई बिना मर्जी या जबरदस्ती के जमीन नहीं हड़प पाएगा। इसके अलावा धर्मांतरण का कुचक्र नहीं चलने दिया जाएगा। क्योंकि, आदिवासी बहन-बेटियों से शादी करवाकर जमीन उनके नाम करवा ली जाती है। आदिवासी की जमीन पर खदान की अनुमति के लिए ग्रामसभा का अप्रूवल लगेगा।

तालाब प्रबंधन और सिंचाई व्यवस्था का जिम्मा ग्रामसभा के पास रहेगा

सीएम ने कहा कि, आदिवासी ग्रामों में बने तालाबों में मछली पालन आदि का जिम्मा ग्रामसभा के पास रहेगा। उसकी परमिशन भी ग्रामसभा देगी, न कि भोपाल से मिलेगी। इसके अलावा 100 एकड़ जमीन तक के तालाबों से सिंचाई व्यवस्था का जिम्मा भी ग्रामसभा के पास रहेगा। जो लोग काम की तलाश में बाहर जाते है, उन्ही ग्रामसभा को जानकारी देना होगी। ताकि, बाहर के जिले या प्रदेश में उनके साथ अनहोनी हो तो मदद की जा सकें। कोई भी व्यक्ति उन्हें बंधक बनाकर काम नहीं करवा सकेंगा।

मनरेगा के मस्टर रोल को ग्रामसभा में रखना पड़ेगा

शिवराज ने मंच से कहा कि, मनरेगा में भ्रष्टाचार होता है। 100 मजदूरों के नाम से राशि निकाली जाती है और काम सिर्फ 50 लोग ही कर रहे होते हैं। ऐसे में मस्टर रोल यानी हाजिरी रजिस्टर को ग्रामसभा में रखकर जनता को बताना पड़ेगी। अनुसूचित गांवों में शराब और भांग की दुकान के लिए ग्रामसभा तय करेगी कि खुलेगी या नहीं। कई किसान लोग साहूकार से कर्ज लेते हैं, इसके लिए साहूकार के पास लाइसेंस होना चाहिए। ब्याज की दर सीमित होना चाहिए। गांवों में शांति और विवाद निवारण समिति बनेगी, जो छोटे विवादों को सुलझाएगी ताकि मामला पुलिस थाना तक नहीं पहुंचे।

चिंता की जरूरत नहीं, प्रदेश में 4 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद उपलब्ध

प्रदेश में प्रतिदिन आ रही है 10 रैक खाद

कृषि विभाग में 4361 पदों पर होगी भर्ती, गांव में मिलेगी खाद

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने खाद और कृषि विभाग में भर्ती को लेकर बड़ा ऐलान किया है। कमल पटेल ने कहा कि पर्याप्त मात्रा में खाद मौजूद, चिंता की जरूरत नहीं, प्रदेश में 4 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद उपलब्ध है। किसानों की व्यवहारिक समस्याओं को देखते हुए सरकार गांव में खाद उपलब्ध कराएगी। वही कृषि विभाग में 4 हजार 361 पदों पर भर्ती होगी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि प्रदेश में प्रतिदिन 10 रैक खाद आ रही है। जिलों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जा रही है। इस वर्ष में 21 नवम्बर तक 36 लाख 63 हजार मीट्रिक टन खाद प्राप्त हो चुका है। गत वर्ष इसी अवधि में नवम्बर तक 29 लाख 13 हजार मीट्रिक टन खाद की आपूर्ति हुई थी। डिफाल्टर और अऋणी किसानों को नगद में खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। किसानों को खाद के लिये लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गांव में ही खाद का ट्रक पहुंचाया जायेगा।

केन्द्र को दिया धन्यवाद

कृषि मंत्री पटेल ने कहा है कि केन्द्र एवं राज्य सरकार किसानों के हित में निरंतर कार्य कर रही है। किसानों को यूरिया एवं डीएपी पर सब्सिडी का लाभ देकर, व्यय केन्द्र सरकार स्वयं वहन कर रही है। केन्द्र सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली 71 हजार करोड़ रूपये की सब्सिडी बढ़ कर 2 लाख करोड़ रूपये से अधिक हो गई है। केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के लिये उर्वरक एवं सब्सिडी व्यवस्था के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और उर्वरक मंत्री मनसुख भाई मंडाविया का आभार व्यक्त किया है।

हेल्पलाइन नंबर जारी

उन्होंने कहा कि खाद वितरण के लिये पीओएस मशीनों की व्यवस्था कर दी गई है। खाद की कोई कमी नहीं है। असुविधा होने पर किसानों का सच्चा साथी- 'कमल सुविधा केन्द्र' के दूरभाष क्रमांक- 0755-2558823 पर शिकायत कर सकते हैं। तत्काल व्यवस्था की जायेगी।

विभाग में 4361 शासकीय पदों पर होगी भर्ती

कृषि मंत्री पटेल ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये कृषि विभाग में भी 4 हजार 361 शासकीय पदों पर भर्ती की जायेगी। कृषि विभाग में 3 हजार 844 और उद्यानिकी विभाग में 517 पद मिलाकर कुल 4 हजार 361 पदों पर भर्ती की जायेगी। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में प्रति माह लाखों लोगों को स्व-रोजगार से जोड़ रही है।

प्रदेश का पहला जिला बना

शाजापुर स्मार्ट फर्टिलाईजर डिस्ट्रीबुशन एप का शुभारंभ

शाजापुर। शाजापुर प्रदेश का प्रथम जिला बना है जहां कृषकों को फसल की पैदावार हेतु आवश्यक खाद की मांग एवं वितरण एप के माध्यम से होगी। एप के माध्यम से अपनी पसंद की खाद की मांग एवं उसके वितरण से कृषकों और समितियों को लाभ भी होगा। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कलेक्टर व प्रशासक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक दिनेश जैन ने स्मार्ट फर्टिलाईजर डिस्ट्रीबुशन एप का शुभारंभ किया।

कलेक्टर श्री जैन ने बताया कि कृषकों को खाद प्राप्त करने के लिए मोबाईल पर ही सूचना मिलेगी और एप के माध्यम से ही कौन-कौन सी खाद बुक की है यह भी देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि कृषक अपने घर बैठे-बैठे एप के माध्यम से खाद की मांग भेज सकते हैं। सोसायटी में कौन-कौन सी खाद उपलब्ध है इसकी जानकारी भी मिलती रहेगी। किसानों को सुविधा होगी कि कितने रकबे में कितना खाद लगेगा, गणना भी ऑटोमेटिक होगी। साथ ही इस एप के माध्यम से खाद प्राप्ति हेतु कब सोसायटी जाना है, इसकी सूचना भी मिलेगी। इसमें छोटे कृषकों को प्रथमिकता मिलेगी और सोसायटी में परमिट बनने में लगने वाले समय की बचत होंगी साथ ही परमिट भी ऑटोमेटिक बनेंगा।

101 को मिला 50 हजार रूपए का ऋण

पीएम स्व निधि योजना में ग्वालियर देश में दूसरे स्थान पर

ग्वालियर। जागत गांव हमार

देशवासियों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने में मदद देने के लिए चल रही पीएम स्व निधि योजना में ग्वालियर भारत में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। पीएम स्व निधि योजना के तहत ग्वालियर नगर निगम द्वारा अभी तक लगभग 32500 लोगों को ऋण दिलाने में मदद की गई है। इनमें से 101 लोगों ने प्रथम बार 10 हजार एवं द्वितीय बार 20 हजार का ऋण चुका दिया। इसके बाद इन लोगों को इनकी जरूरत के हिसाब से बैंक ने 50 हजार का ऋण दिया है। निगमायुक्त किशोर कन्याल ने बताया कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत कोरोना काल के समय लोगों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए पीएम स्व निधि योजना संचालित की गई। दीनदयाल राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत इसमें सर्वप्रथम लोगों को बिना किसी गारंटी के 10 हजार रुपए का ऋण दिया गया। इसकी किश्तें चुकाने के बाद हितग्राहियों को बैंकों द्वारा 20 हजार का ऋण आवंटित किया।

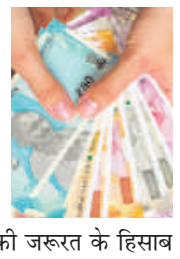

101 हितग्राहियों ने 20 हजार का ऋण लेने के बाद चुका दिया

जब 20 हजार के ऋण की किश्तें चुकता करने के बाद बैंक द्वारा 50 हजार का ऋण हितग्राहियों को आवंटित किया गया है। अपर आयुक्त मुकुल गुप्ता व उपायुक्त मिनी अग्रवाल ने बताया कि अभी तक 101 हितग्राहियों ने 20 हजार का ऋण लेने के बाद चुका दिया है। इन सभी को बैंकों द्वारा 50 हजार का ऋण आवंटित किया गया है।

कई राज्यों के 217 कृषकों को किया जा चुका है प्रशिक्षित

अब मल्टीक्राप छिंदवाड़ा में होगी मोती की खेती

छिंदवाड़ा। जागत गांव हमार

जवाहर लाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय अंतर्गत कृषि विज्ञान केन्द्र चंदनगांव मे वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ सुरेन्द्र पन्नासे के सफल प्रयासों एवं मार्गदर्शन से मोती की खेती की जा रही है। जिस हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली से, केन्द्र मे पदस्थ चंचल भार्गव, कायक्रम सहायक द्वारा आदिवासी उपयोजना प्राप्त की गई है। चंचल भार्गव ने बताया कि हमारे जिले के किसान सभी प्रकार की खेती करते हैं, लेकिन आजकल मोती की खेती चलन तेजी से बढ़ रहा है। कम मेहनत और लागत में अधिक मुनाफे का सौदा साबित हो रहा है। अभी तक उड़ीसा के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वॉटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर (उड़ीसा) में मोती की खेती का प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन अब देश में भी कई जगह पर इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे युवाओं को बेहतर रोजगार मिलेगा।

चंदनगांव में की जा रही 8000 सीपों से मोती की खेती

इसी तारतम्य मे कृषि विज्ञान केन्द्र चंदनगांव छिंदवाड़ा में 8000 सीपों से मोती की खेती की जा रही है। जिस हेतु माह मार्च 2021 मे 8000 सीपों मे शल्य क्रिया कर मोती के बीजों को डाला गया है। मोती की खेती के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। कम से कम 100-80-12 फीट या बड़े आकार के तालाब में मोतियों की खेती की जा सकती है।

कैसे करें मोती की खेती

मोती संवर्धन के लिए 0.4 हेक्टेयर जैसे छोटे तालाब में अधिकतम 15000 सीप से मोती उत्पादन किया जा सकता है। खेती शुरू करने के लिए किसान को पहले तालाब, नदी आदि से सीपों को इकट्ठा करना होता है या फिर इन्हे खरीदा भी जा सकता है। इसके बाद प्रत्येक सीप में छोटी-सी शल्य क्रिया के बाद इसके भीतर चार से छह मिमी व्यास वाले साधारण गोल या डिजायनदार बीड जैसे गणेश, बुद्ध, पुष्प आकृति आदि डाले जाते हैं। फिर सीप को बंद किया जाता है। इन सीपों को नायलॉन बैग में 2 दिनों तक एंटी-बायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है। रोजाना इनका निरीक्षण किया जाता है और मृत सीपों को हटा लिया जाता है। अब इन सीपों को तालाबों में डाल दिया जाता है। इसके लिए इन्हें नायलॉन बैगों में रखकर (दो सीप प्रति बैग) बांस के सहारे लटका दिया जाता है और तालाब में एक मीटर की गहराई पर छोड़ दिया जाता है। प्रति हेक्टेयर 20 हजार से 30 हजार सीप की दर से इनका पालन किया जा सकता है। अन्दर से निकलने वाला पदार्थ बीड के चारों ओर जमने लगता है जो अन्त में मोती का रूप लेता है। लगभग 15-18 माह बाद सीप को चीर कर मोती निकाल लिया जाता है। एक सीप की लागत लगभग 35 से 40 रुपए की आती है। बाजार में एक मिमी से 20 मिमी सीप के मोती का दाम करीब 100 रूपये से लेकर 1500 रूपये होता है।

विदेशी बाजार में मिलती है अच्छी कीमत

आजकल डिजायनर मोतियों को खासा पसन्द किया जा रहा है जिनकी बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। भारतीय बाजार की अपेक्षा विदेशी बाजार में मोतियों का निर्यात कर काफी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। सीप से मोती निकाल लेने के बाद सीप को भी बाजार में बेंचा जा सकता है। सीप द्वारा कई सजावटी सामान तैयार किये जाते है। सीपों से कन्नौज में इत्र का तेल निकालने का काम भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। जिससे सीप को भी स्थानीय बाजार में तत्काल बेचा जा सकता है। सीपों से नदीं और तालाबों के जल का शुद्धिकरण भी होता रहता है जिससे जल प्रदूषण की समस्या से काफी हद तक निपटा जा सकता है।

बेरोजगारों के लिए बन सकता है वरदान

केन्द्र के प्रमुख डॉ. पन्नासे ने बताया कि केन्द्र द्वारा ग्रामीण नवयुवकों एवं किसानों को निरंतर मोती की खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे काफी हद तक बेरोजगार नवयुवकों को भी रोजगार दिया जा सकता है। मृत सीपों का चूरा बनाकर कुक्कुट को देने से कैल्शियम की पूर्ति भी की जा सकती है। आज दिनांक तक कृषि विज्ञान केन्द्र चंदनगांव द्वारा मध्यप्रदश के विभिन्न जिलों के अतिरिक्त अन्य राज्यों जैसे पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हरियाणा आदि के कुल 217 कृषकों को मोती की खेती संबंधित प्रशिक्षण दिया जा चुका है। आगे अन्य प्रशिक्षण भी प्रस्तावित है।

कृषि वैज्ञानिक के अनुसार गेहूं फसल में आवश्यक उर्वरक और उसकी मात्रा

ग्वालियर। गेहूं की बुवाई शुरू हो चुकी है। अच्छा उत्पादन लेने के लिए सिंचाई और खाद का उचित प्रबंधन होना आवश्यक है। कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर के कृषि वैज्ञानिक डॉ राज सिंह कुशवाह के अनुसार गेहूं की फसल में अच्छे उत्पादन के लिए खाद की मात्रा इस प्रकार होनी चाहिए। अर्धसिंचित- 60 किलो नत्रजन, 40 किलो स्फुर, 20 किलो पोटाश साथ ही 10 से 12 टन पकी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। सिफारिश के अनुसार तत्वों की पूर्ति हेतु उनकी मात्रा किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर- डीएपी 87 किलो, यूरिया 118 किलो, पोटाश 34 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग करें। सिंचित अवस्था में- नत्रजन 100 किलो, स्फुर 60 किलो, पोटाश 40 किलो प्रति हेक्टेयर साथ ही 12 से 14 टन पकी हुई गोबर की खाद का अवश्य उपयोग करें। सिफारिश के अनुसार तत्वों की पूर्ति हेतु मात्रा किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर-डी ए पी 130 किलो, यूरिया 166 किलो, पोटाश 67 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग करें। 1 हेक्टेयर 5 बीघा का होता है। ऊपर दी गई मात्राओं का 5 में भाग देकर एक बीघा का डोज निकाल सकते हैं।

कम क्षेत्रफल में फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने पर विभाग का जोर

पॉली हाउस, शेड नेट एवं उच्च कोटि की सब्जी उत्पादन के लिए अनुदान

भोपाल। जागत गांव हमार

कम क्षेत्रफल में फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार संरक्षित खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान कर ग्रीन हाउस/ शेड नेट हाउस/ प्लास्टिक टनल/ प्लास्टिक मल्चिंग इत्यादि को प्रोत्साहित कर रही है ताकि किसान नियंत्रित वातावरण में ताजी सब्जियों एवं फूलों की खेती वर्ष भर कर सकें। इस कड़ी में मध्य प्रदेश के उद्यानिकी विभाग द्वारा चयनित ज़िलों में सरंक्षित खेती पर अनुदान हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं।

मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग द्वारा पॉली हाउस, शेड नेट हाउस तथा उच्च कोटि की सब्जी उत्पादन के लिए पूर्व में 12 जिलों के किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे परंतु 6 जिलों से किसी भी प्रकार की आवेदन 11 नवंबर 2022 तक प्राप्त नहीं हुए हैं। इसको देखते हुए विभाग ने दोबारा लक्ष्य जारी किए हैं।

इन जिलों के लिए जारी किए गए हैं लक्ष्य

उद्यानिकी विभाग मध्य प्रदेश ने राज्य पोषित व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना अंतर्गत राज्य के तीन ज़िलों भोपाल, नरसिंहपुर एवं दतिया ज़िलों के लिए लक्ष्य जारी किए हैं। यह लक्ष्य शेड नेट हाउस, पॉली हाउस एवं उच्च कोटि की सब्जी उत्पादन के लिए जारी किए गए हैं। जारी लक्ष्य के विरुद्ध भोपाल, नरसिंहपुर तथा दतिया जिलों के सामान्य, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं।

संरक्षित खेती के लिए दिया जाने वाला अनुदान

संरक्षित खेती हेतु प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों को पॉली हाउस, शेड नेट हाउस एवं उच्च कोटि की सब्जी उत्पादन हेतु 50 प्रतिशत की दर से अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। इसमें अलग-अलग क्षेत्रफल के पॉली हाउस, शेड नेट के लिए शासन द्वारा अलग-अलग लागत निर्धारित की गई है जिस पर शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है। इसी तरह योजना अंतर्गत पॉली हाउस/ शेड नेट हाउस में उगाई जाने वाली उच्च कोटि की सब्ज़ियों की खेती और रोपण सामग्री के लिए शासन द्वारा प्रति इकाई 140 रूपये की लागत निर्धारित की गई है। जिस पर लाभार्थी किसान को 50 प्रतिशत अधिकतम 70 रूपये का अनुदान दिया जायेगा।

अनुदान हेतु आवेदन कहाँ करें

योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के पात्र किसान उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्य प्रदेश के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसानों को आवेदन करते समय अपने पास फ़ोटो, आधार, खसरा नम्बर/बी 1/ पट्टे की प्रति, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र आदि आवश्यक दस्तावेज अपने पास रखना होगा। इसके अलावा किसान भाई यदि योजना के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उद्यानिकी विभाग की वेबसाइट पर देख सकते हैं अथवा विकासखंड/जिला उद्यानिकी विभाग में संपर्क करें। किसानों को आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर जाकर करना होगा।

सब्सिडी पर हार्वेस्टर एवं स्ट्रॉ बेलर कृषि य

सब्सिडी पर हार्वेस्टर एवं स्ट्रॉ बेलर कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन करें

भोपाल। जागत गांव हमार

किसान आधुनिक कृषि यंत्रों की मदद से कम समय में अधिक से अधिक कृषि कार्य कर सकें इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। इस कड़ी में मध्य प्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा राज्य में किसानों को अनुदान पर ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर एवं हाइड्रॉलिक प्रेस स्ट्रॉ बेलर (ट्रेक्टर चलित) हेतु आवेदन माँगे गए हैं। कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा इन कृषि यंत्रों के लिए आवेदन माँग के अनुसार श्रेणी के तहत रखे गए हैं। अत: इनके लिए अभी जिले वार लक्ष्य जारी नहीं किए गए हैं, किसानों की माँग के बाद ही लक्ष्य आवंटित किए जाएंगे। आइए जानते हैं इन कृषि यंत्रों के लिए किसान किस तरह आवेदन कर सकते हैं एवं यंत्रो पर सरकार कितनी सब्सिडी देगी।

पैडी हार्वेस्टर एवं स्ट्रॉ बेलर पर सब्सिडी कितना अनुदान

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को दिए जाने वाले अनुदान की मात्रा किसान वर्ग के अनुसार होती है, जो की 40 से 50 प्रतिशत तक है। राज्य में एक किसान को किस कृषि यंत्र पर कितनी सब्सिडी मिलेगी यह जानकारी किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैल्क्युलेटर पर देख सकते हैं। हाइड्रॉलिक प्रेस स्ट्रॉ बेलर (ट्रेक्टर चलित) की कीमत लगभग 17,00,000 रूपये तक होती है, किसान इसमें अपने स्तर पर डीलर से मोलभाव भी कर सकते हैं। इस पर किसान को अधिकतम 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी या अधिकतम 7,00,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। वहीं ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर का कीमत लगभग 25 लाख रुपए तक होती है, किसान इसमें अपने स्तर पर डीलर से मोलभाव भी कर सकते हैं। जिसपर सरकार द्वारा अधिकतम 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। जो ट्रैक टाइप 6-8 फ़ीट कटरबार के लिए अधिकतम 11,00,000 लाख रुपए की राशि एवं ट्रैक टाइप 6-8 फ़ीट कटरबार से कम के लिए अधिकतम 7,00,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। किसानों को जमा करना होगा डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) ऊपर दिये हुए कृषि यंत्रों के लिए डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवाना अनिवार्य है। जहां सभी कृषि यंत्र के लिए डिमांड ड्राफ्ट की राशि 5000 रूपये निर्धारित की गई है। किसानों को यह डिमांड ड्राफ्ट जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाना होगा। आवेदन के बाद यदि किसान का चयन नहीं होता है तो यह धरोहर राशि किसानों को लौटा दी जाएगी परंतु चयन होने के बाद यदि किसान कृषि यंत्र नहीं खरीदता है तो यह धरोहर राशि उस किसान को नहीं दी जाएगी।

कहां करें आवेदन

सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन किसान भाई ऑनलाइन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं, आवेदन के समय उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर ओटीपी वन टाइम पासवर्ड प्राप्त होगा, इसलिए किसान अपना मोबाइल अपने पास रखें। किसान अधिक जानकारी के लिए अपने ज़िले के कृषि विभाग या कृषि यंत्री कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं या कृषि अभियांत्रिकी संचनालय के पोर्टल https://dbt.mpdage.org/ पर जाकर देख सकते हैं।

रुकेगी फसल की बर्बादी, कृषि केंद्र या सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं

क्रॉप डॉक्टर ऐप घर बैठे कर देगा फसल में कीट और रोगों की पहचान

भोपाल। जागत गांव हमार

किसानों फसलों में रोग लगने या कीटों के हमले के बाद बचाव के लिए कृषि केंद्र या सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे घर बैठे ही मोबाइल से फोटो क्लिक कर फसलों में लगने वाली सारी बीमारियों का पता लगा सकते हैं। दरअसल, स्विटजरलैंड की कृषि रसायन कंपनी सिंजेंटा ने फसल पर कीट या रोग के हमले की पहचान करने के लिए अपने मोबाइल ऐप में एक फीचर पेश किया है। इस फीचर की खासियत है कि यह महज रोग ग्रसित फसलों की फोटो से ही उसके समाधान के बारे में जानकारी दे देता है।.

कृषि रसायन कंपनी सिंजेंटा ने बयान में कहा कि इस साल अगस्त में पेश हुए उसके फसलवार 'ग्रोवर ऐप' में नया फीचर 'क्रॉप डॉक्टर' पेश किया है। सिंजेंटा इंडिया के प्रबंध निदेशक (एमडी) और कंट्री प्रमुख सुशील कुमार ने कहा कि वैश्विक स्तर पर किसानों को जलवायु परिवर्तन, मिट्टी के कटाव और जैव विविधता के नुकसान सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नया जोड़ा गया फीचर किसानों के लिए बहुत मददगार होगा।

सिंजेंटा उत्पादों के बारे में जानकारी देगा

सिंजेंटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के किसान केंद्रित पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख सचिन कामरा ने कहा कि किसानों को इस फीचर का उपयोग करने के लिए केवल ग्रोवर ऐप से एक फोटो क्लिक करने की जरूरत है। क्रॉप डॉक्टर कीटों या बीमारियों की पहचान करेगा और उपयोग किए जाने वाले सिंजेंटा उत्पादों के बारे में जानकारी देगा।

10 भषाओं में लॉन्च हुआ ऐप

जानकारी के मुताबिक, 'ग्रोवर ऐप' को हिन्दी, तेलुगु, बंगाली, उड़िया, कन्नड़, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती और मराठी सहित 10 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। महज 75 दिनों में ही 3 लाख से अधिक किसानों ने इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया है। वहीं, सचिन कामरा ने कहा कि इस 'ग्रोवर ऐप' के इस्तेमाल से फसलों का उपज बढ़ जाएगा। साथ ही किसानों की आमदनी में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि साथ ही किसानों को उनकी फसलों की सिंचाई, खाद और फसल सुरक्षा उत्पादों को लागू करने में मदद और मार्गदर्शन करके उन्हें सशक्त भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इस ऐप में धान, टममाटर और मक्का सहित 10 और प्रमुख फसलों को जोड़ा जाएगा।

सामाजिक-आर्थिक विकास में डेयरी उद्योग का योगदान

» डॉ. बालेश्वरी दीक्षित
» डॉ. डॉ. मनु दीक्षित
» डॉ. डॉ. अर्पिता श्रीवास्तव
» डॉ. डॉ. अंजय
» डॉ. डॉ. सपना शर्मा
-पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, रीवा

छोटे पैमाने के डेयरी किसानों के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया में डेयरी उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। दूध और दूध उत्पादों की उपलब्धता में निरंतर वृद्धि के साथ भारत 1998 से दुनिया भर में डेयरी उत्पादों का अग्रणी उत्पादक और उपभोक्ता रहा है। डेयरी गतिविधियां ग्रामीण भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अनिवार्य हिस्सा हैं, जो रोजगार और आय के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में काम करती हैं। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी गोजातीय आबादी भी है। हालांकि, अन्य प्रमुख डेयरी उत्पादकों की तुलना में प्रति पशु दूध उत्पादन काफी कम है। इसके अलावा, भारत में लगभग सभी डेयरी उत्पादों की घरेलू रूप से खपत होती है, जिनमें से अधिकांश को तरल दूध के रूप में बेचा जाता है। इसके कारण, भारतीय डेयरी उद्योग में मूल्यवर्धन और समग्र विकास की जबरदस्त क्षमता है।

भारत में डेयरी बाजार 2021 में 13,174 बिलियन के मूल्य पर पहुंच गया। आगे देखते हुए, IMARC समूह को उम्मीद है कि 2027 तक बाजार 30,840 बिलियन तक पहुंच जाएगा, जो 2022-2027 के दौरान 14.98प्रतिशत के सीएजीआर पर प्रदर्शित होगा।

भारत सरकार ने देश में डेयरी क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं और पहलों की शुरुआत की है। भारत में डेयरी उत्पादों का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु है। भारतीय डेयरी उद्योग में प्रतिस्पर्धा हमेशा मजबूत रही है। अमूल, मदर डेयरी, उड़ीसा स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन, दूधसागर डेयरी, आविन और क्वालिटी लिमिटेड भारत में डेयरी उद्योग के कुछ प्रमुख प्रोड्यूसर्स हैं।

दूध के महत्व और लाभों को दर्शाने के लिए हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस डॉ वर्गीज कुरियन की जयंती पर मनाया जाता है, जिन्हें श्वेत क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), भारतीय डेयरी संघ (आईडीए) सहित 22 राज्यों के दुग्ध महासंघ सहित देश के डेयरी प्रमुखों द्वारा इस दिन को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में चुना गया था। भारतीय डेयरी संघ ने 2014 में पहली बार राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाने की पहल की।

दुनिया की सबसे बड़ी मवेशी आबादी होने के बावजूद, देश में सालाना 21 मीट्रिक टन से कम दूध का उत्पादन होता है। 1950 और 1960 के दशक के दौरान, भारत में दूध की कमी थी और वह आयात पर निर्भर था। वार्षिक उत्पादन वृद्धि कई वर्षों से नकारात्मक थी। स्वतंत्रता के बाद पहले दशक के दौरान, दुग्ध उत्पादन ने 1.64प्रतिशत का सीएजीआर दर्ज किया, जो 1960 के दशक के दौरान 1.15प्रतिशत तक गिर गया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की स्थापना 1965 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की सहायता के लिए की गई थी, जिसे पूरे देश में डेयरी सहकारी समितियों के आनंद पैटर्न की स्थापना के चरणों में निष्पादित किया जाना था। एनडीडीबी के उद्घाटन अध्यक्ष डॉ वर्गीज कुरियन थे, जिन्हें भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। डॉ. कुरियन और उनकी टीम ने परियोजना के शुभारंभ पर काम करना शुरू कर दिया, जिसने पूरे देश में मिल्क शेड्स में आनंद पैटर्न सहकारी समितियों की स्थापना करने का आह्वान किया, जिससे दुग्ध सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित और खरीदे गए तरल दूध को शहरों में ले जाया जाएगा। वर्गीस कुरियन एक सामाजिक उद्यमी थे, जिनके बिलियन-लीटर आइडिया, ऑपरेशन फ्लड के विजन ने डेयरी फार्मिंग को भारत का सबसे बड़ा आत्मनिर्भर उद्योग और ग्रामीण आय का एक तिहाई प्रदान करने वाला सबसे बड़ा ग्रामीण रोजगार क्षेत्र बना दिया। उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार (1963), विश्व खाद्य पुरस्कार (1989), कृषि रत्न (1986), पद्म भूषण (1966) और पद्म श्री (1965) सहित कई सम्मान प्राप्त हुए। दुनिया में सबसे बड़ा कृषि डेयरी विकास कार्यक्रम, ऑपरेशन फ्लड, द्वारा दूध की कमी वाला देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया।

ऑपरेशन फ्लड: ऑपरेशन फ्लड से भारत दूध और दुग्ध उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। नेशनल मिल्क ग्रिड के माध्यम से, ऑपरेशन फ्लड ने 700 कस्बों और शहरों में उपभोक्ताओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले दूध का उपयोग करना संभव बना दिया। सहकारी ढांचे के कारण, किसानों के लिए दूध और दुग्ध उत्पादों का उत्पादन और वितरण स्वयं करना आर्थिक रूप से संभव था। इसके अतिरिक्त, इसने आयातित ठोस दूध पर भारत की निर्भरता को समाप्त कर दिया। 1950-51 में केवल 17 मीट्रिक टन दूध का उत्पादन हुआ था। ऑपरेशन फ्लड शुरू होने से पहले, दूध का उत्पादन 1968-69 में केवल 21.2 मीट्रिक टन था, लेकिन 1979-1980 तक बढ़कर 30.4 मीट्रिक टन, 1989-1990 तक 51.4 मीट्रिक टन और 2020-21 तक 209.96 मीट्रिक टन हो गया। भारत में दैनिक दूध की खपत तीन दशकों में - 1980, 1990 और 2000 के दशक में - 1970 में 107 ग्राम प्रति व्यक्ति के निचले स्तर से बढ़कर 2020-21 में 427 ग्राम प्रति व्यक्ति हो गई।

1970 से 1980 तक प्रथम चरण: इसे विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से यूरोपीय संघ द्वारा बनाए गए बटर ऑयल और स्किम मिल्क पाउडर के दान द्वारा समर्थित किया गया था। ऑपरेशन फ्लड ने चार महानगरों में मदर डेयरी बनाई और इस चरण के दौरान भारत

के 18 सर्वश्रेष्ठ मिल्क शेड्स को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा।

1981 से 1985 तक दूसरा चरण: इस चरण के दौरान 18 से 136 दूध शेड जोड़े गए। कुल 290 शहरी बाजारों ने भी अपना दूध वितरण बढ़ाया। और 1985 के अंत तक, 4.25 मिलियन दुग्ध उत्पादक 43,000 ग्राम सहकारी समितियों के आत्मनिर्भर नेटवर्क का हिस्सा थे। 1989 तक, 22,000 टन से बढ़कर 140,000 टन घरेलू दूध पाउडर का उत्पादन हो चुका था।

1985 से 1996 तक तीसरा चरण: इस समय के दौरान, डेयरी सहकारी समितियों ने बाजार में दूध की आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए अपने बुनियादी ढांचे का विकास और विस्तार किया। द्वितीय चरण के दौरान पहले से ही स्थापित 42,000 डेयरी सहकारी समितियों में 30,000 नई डेयरी सहकारी समितियों को शामिल करके, इस चरण ने भारत में डेयरी सहकारी आंदोलन को मजबूत किया। मिल्कशेड में महिलाओं की भागीदारी, जो 1988-1989 में बढ़कर 173 हो गई, और महिला डेयरी सहकारी समितियों में भी काफी वृद्धि हुई। महिला डेयरी सहकारी नेतृत्व कार्यक्रम (डब्ल्यूडीसीएलपी) की स्थापना 1995 में सहकारी समितियों, संघों और संघों में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने के साथ-साथ डेयरी सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लक्ष्य के साथ एक पायलट कार्यक्रम के रूप में की गई थी। पशु पोषण और स्वास्थ्य में अनुसंधान और विकास भी थे। इस चरण के दौरान जोर दिया। इलेरिओसिस के लिए एक टीका, प्रोटीन फ़ीड से बचने और यूरिया-शीरा खनिज ब्लॉक जैसे नवाचारों ने दुधारू पशुओं को अधिक दूध देने में मदद की। भारत में सबसे बड़ा आत्मनिर्भर उद्योग वर्ष 2014 रहा। इस दिन की शुरुआत इंडियन डेयरी एसोसिएशन (आईडीए) द्वारा की गई थी। भारत में डेयरी क्षेत्र में अवसरों को और बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई कुछ पहलें इस प्रकार हैं-

राष्ट्रीय गोकुल मिशन: दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए, जिससे डेयरी से किसानों की आय में वृद्धि होगी, राष्ट्रीय गोकुल मिशन (जिसका उद्देश्य मवेशियों की आबादी में आनुवंशिक रूप से सुधार करना और देशी मवेशियों की नस्लों को बढ़ावा देना और संरक्षित करना है) को कार्यान्वयन के लिए पांच साल का विस्तार दिया गया है। मिशन के तहत, किसानों के पास अब उनके दरवाजे पर कई अत्याधुनिक तकनीकों तक पहुंच है, जिसमें सेक्स-सॉर्टेड वीर्य, आईवीएफ तकनीक और जीनोमिक चयन शामिल हैं। नियोजित कार्यक्रम के कार्यान्वयन के साथ दूध उत्पादन 2019-20 में 198.4 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 2024-25 में 300 मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगा। प्रति पशु प्रति वर्ष औसतन 1,200 किग्रा. के दूध उत्पादन में वृद्धि से आठ करोड़ डेयरी उत्पादकों को सीधे तौर पर मदद मिलेगी।

डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीडीडी): एनपीडीडी फरवरी 2014 से अस्तित्व में है और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी या राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले दूध के उत्पादन के साथ-साथ दूध और दूध उत्पादों की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण या मजबूत करना है। जुलाई 2021 में, कार्यक्रम का पुनर्गठन/पुनर्गठन किया गया। 2021-22 से 2025-26 तक, पुन: डिज़ाइन की गई एनपीडीडी योजना रुपये के बजट के साथ लागू की जाएगी। कार्यक्रम के उद्देश्यों में दूध और दूध से बने उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाना और खरीद, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और विपणन के लिए संगठित बाजार हिस्सेदारी बढ़ाना शामिल है।

डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डीईडीएस)

पिछले तीन वर्षों में भारत के डेयरी उत्पादों के निर्यात में लगातार वृद्धि देखी गई है। 2021-22 में, भारत ने दुनिया को 108,711 मीट्रिक टन डेयरी उत्पादों का कुल रु 2,928.79 करोड़, बांग्लादेश, यूएई, बहरीन, मलेशिया, सऊदी अरब और कतर प्रमुख में निर्यात किया। ऑपरेशन फ्लड के बाद, भारत में कई ग्रामीण परिवारों ने अपनी आय के मुख्य स्रोत के रूप में डेयरी और पशुपालन उद्योगों की ओर रुख किया। लगभग 25 वर्षों तक, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश रहा है। इसने पिछले 20 वर्षों में दोगुना दूध का उत्पादन किया है। राष्ट्रीय डेयरी योजना (स्थायी विकास पर केंद्रित उद्योग के लिए एक रूपरेखा) के साथ-साथ जन धन योजना और स्टार्ट-अप इंडिया पहल जैसे सामान्य सशक्तिकरण कार्यक्रम, सरकार के उन उपायों में से थे, जिन्होंने डेयरी खेती के लिए बुनियादी ढांचे में मदद की। भारत के डेयरी क्षेत्र को बड़े पैमाने पर उत्पादन के बजाय बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए जाना जाता है।

मध्य प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा में मजदूरों को सबसे कम दिहाड़ी, लिस्ट में केरल सबसे ऊपर

बढ़ती महंगाई, कम होती दिहाड़ी, कैसे होगा गुजारा?

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 19 नवंबर, 2022 को जारी रिपोर्ट 'हैंडबुक ऑफ स्टेटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स' से पता चला है कि मध्य प्रदेश, गुजरात और त्रिपुरा में बढ़ती महंगाई के बीच 2021-22 में सबसे कम दिहाड़ी मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ दूध, फल, सब्जियों और अन्य जरूरी सामान की कीमतें आसमान छू रहीं हैं।

रिजर्व बैंक के अनुसार इन राज्यों में कृषि, निमाज़्ण, बागवानी और गैर-कृषि क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में मजदूरी कर रहे श्रमिकों की दिहाड़ी राष्ट्रीय औसत से भी कम है। पता चला है कि जहां खेती में काम कर रहे पुरुष मजदूरों को 217.8 रुपए प्रति दिन के हिसाब से मजदूरी मिल रही है। वहीं गुजरात में यह मजदूरी 220.3 रुपए प्रति दिन है। इन राज्यों के बाद ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार का नंबर आता है।

वहीं दूसरी तरफ केरल के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानी में लगे मजदूरों को देश में सबसे ज्यादा 726.8 रुपए की दिहाड़ी मिल रही है। इसके बाद जम्मू-कश्मीर में 524.6 रुपए, हिमाचल प्रदेश 457.6 रुपए और तमिलनाडु में मजदूरों को हर दिन के हिसाब से 445.6 रुपए मिलते हैं।

रिपोर्ट से पता चला है कि देश में हर दिन कृषि क्षेत्र में लगे मजदूरों को औसतन 323.32 रुपए मजदूरी के रूप में मिलते हैं। वहीं अध्ययन किए गए 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 50 फीसदी में श्रमिकों को राष्ट्रिय औसत से ज्यादा मजदूरी मिलती है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मेघालय, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु शामिल हैं।

वहीं यदि कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की बात करें तो वहां भी स्थिति कृषि क्षेत्र जैसी ही है। जहां त्रिपुरा में प्रति मजदूर औसतन 250 रुपए दिहाड़ी है वहीं मध्य प्रदेश में यह 266.7 रुपए और गुजरात में 295.9 रुपए दर्ज की गई है। वहीं यदि केरल की बात करें तो वहां ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण क्षेत्र में लगे मजदूर को हर दिन औसतन 837.7 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर (519.8 रुपए) और तमिलनाडु (478.6) में भी इस क्षेत्र के मजदूरों की देहाड़ी 450 रुपए से ज्यादा है।

देखा जाए तो आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण मजदूरी में हुई वृद्धि बढ़ती महंगाई के साथ तालमेल बैठाने में विफल रही है। इस बीच जहां खुदरा महंगाई दर 6.77 फीसदी दर्ज की गई। हालांकि देखा जाए तो अक्टूबर में यह सात फीसदी से नीचे गिर गई थी। फिर भी इसके बावजूद यह आरबीआई के दो से छह फीसदी की सहनशीलता सीमा से काफी ऊपर है।

इस बीच सरकार द्वारा गेहूं और चावल के नियाज़्त पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद अक्टूबर 2022 में अनाज और उत्पादों की कीमतों में वृद्धि जारी रही। अक्टूबर 2022 में अनाज की महंगाई नौ साल के उच्चतम स्तर 12.08 फीसदी पर पहुंच गई, जो सितंबर 2022 में 11.53 फीसदी से भी ऊपर थी।

आरबीआई के आंकड़ों में यह भी सामने आया है कि गैर-कृषि क्षेत्र से जुड़े मजदूरों को भी केरल, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मजदूरी मिल रही है। वहीं मध्य प्रदेश, गुजरात और त्रिपुरा में उनकी देहाड़ी सबसे कम है। हालांकि देखा जाए तो 2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान गुजरात में मजदूरी दर में मामूली वृद्धि हुई है। लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में इसमें गिरावट दर्ज की गई है, जबकि त्रिपुरा में भी ऐसा ही हाल है।

किसानों को पर्याप्त बीमा कवच उपलब्ध कराने के प्रयास में सरकार

कृषि और किसान कल्याण सचिव मनोज आहूजा ने कहा कि खेती जलवायु संकट का सीधा शिकार होती है, इसलिये यह जरूरी है कि प्रकृति के उतार-चढ़ाव से देश के कमजोर किसान समुदाय को बचाया जाये। फलस्वरूप, फसल बीमा में बढ़ोतरी संभावित है और इसलिये हमें फसल तथा ग्रामीण/कृषि बीमा के अन्य स्वरूपों पर ज्यादा जोर देना होगा, ताकि भारत में किसानों को पर्याप्त बीमा कवच उपलब्ध हो सके। आहूजा ने कहा कि वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरूआत के बाद, यह योजना सभी फसलों और नुकसानों को समग्र दायरे में ले आई। इसके तहत बुवाई के पहले के समय से लेकर फसल कटाई तक की अवधि को रखा गया है। पहली वाली राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित योजना में इस अवधि को नहीं रखा गया था. उन्होंने कहा कि 2018 में इसकी समीक्षा के दौरान भी कई नई बुनियादी विशेषताएं इसमें जोड़ी गईं, जैसे फसल के नुकसान की सूचना देने का समय 48 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे कर दिया गया। इसमें इस बात को ध्यान में रखा गया कि स्थानीय आपदा आने पर नुकसान के निशान 72 घंटे के बाद या तो विलीन हो जाते हैं या उनकी निशानदेही नहीं हो पाती। इसी तरह, 2020 के संशोधन के उपरान्त, योजना में वन्यजीव के हमले के बारे में स्वेच्छा से पंजीकरण कराने और उसे शामिल करने का प्रावधान किया गया, ताकि योजना को अधिक किसान अनुकूल बनाया जा सके।

आहूजा ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल बीमा को अपनाने की सुविधा दे रही है। साथ ही, कई चुनौतियों का समाधान भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संशोधित योजना में जो प्रमुख बदलाव किये गये हैं, वे राज्यों के लिये अधिक स्वीकार्य हैं, ताकि वे जोखिमों को योजना के दायरे में ला सकें। इसके अलावा किसानों की बहुत पुरानी मांग को पूरा करने के क्रम में सभी किसानों के लिये योजना को स्वैच्छिक बनाया गया है।

हाई कोर्ट ने पूछा क्यों नहीं कराए जा रहे कृषि उपज मंडी समितियों के चुनाव

जबलपुर। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों के चुनाव न कराए जाने के रवैये को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जवाब-तलब कर लिया है। इस सिलसिले में मुख्य चुनाव आयुक्त व मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मंडी बोर्ड) को नोटिस जारी किए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई छह जनवरी, 2023 को निर्धारित की गई है।

मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच युवा मोर्चा के अध्यक्ष मनीष शर्मा सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने

पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि प्रदेश में मंडी समितियों का कार्यकाल जनवरी 2018 में समाप्त हो चुका है। कृषि उपज मंडी अधिनियम की धारा 11 में समितियों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। धारा 57 में सरकार को यह अधिकार है कि आवश्यकता पड़ने पर कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में बढ़ा हुआ कार्यकाल साढ़े तीन साल से ज्यादा नहीं हो सकता। प्रदेश में समितियों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद साढ़े चार साल व्यतीत हो चुके हैं। चुनाव नहीं कराना मतदाताओं के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। सरकार अपने कानूनी दायित्वों का पालन करने में असफल रही है। जनहित में मध्य प्रदेश की मंडी समितियों के चुनाव शीघ्र कराए जाने चाहिए।

लाभार्थियों को लगभग एक लाख रुपये की लागत से शेड, बर्तन, दाना और 100 चूजे दे रही सरकार

सफल रही राज्य सरकार की योजना कड़कनाथ ने जिंदगी में भर दी खुशियां

नौमान खान, झाबुआ। जागत गांव हमार

पौष्टिकता से भरपूर कड़कनाथ मुर्गे की मांग धीरे- धीरे मार्केट में बढ़ती जा रही रहै। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने जनजातीय महिलाओं के लिए कड़कनाथ पालन इकाई की स्थापना करने का योजना बनाई है, ताकि इन्हें रोजगार मुहैया कराया जा सके। खास बात यह है कि राज्य सरकार इस योजना के तहत लाभार्थियों को लगभग एक लाख रुपये की लागत से शेड, बर्तन, दाना और 100 चूजे दे रही है। साथ ही सही तरह से पालन करने के लिए तकनीकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। जानकारी के मुताबिक, 28 दिन के चूजे को टीकाकरण के बाद हितग्राहियों को दिए जा रहे हैं, ताकि इनकी मौत न हो। अगर हितग्राही कड़कनाथ बेचने में समर्थ नहीं है, तो पशुपालन विभाग उनसे अंडे और मुर्गे भी खरीद लेगा। कड़कनाथ को जीआई टैग मिला हुआ है।

मुर्गी की कीमत इससे भी तीन गुना अधिक होती है- उल्लेखनीय है कि कड़कनाथ मुर्गे की त्वचा, पंख, मांस और खून सहति अगं का सारा हिस्सा काला होता है। सफेद चिकन के मुकाबले इसमें कॉलेस्ट्रोल का स्तर काफी कम होता है। फैट की मात्रा कम होने से हृदय और मधुमेह के रोगियों के लिये बहुत फायदेमंद माना जाता है। साथ ही यह रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ कम वसा, प्रोटीन से भरपूर, हृदय-श्वास और एनीमिक रोगी के लिए लाभकारी है। अन्य मुर्गे और उनके अंडों की तुलना में यह काफी मंहगा होता है। इसका एक अंडा लगभग 30 रुपये और मुर्गा 900 से 1100 रूपये प्रति किलो में मिलता है। जबकि मुर्गी की कीमत इससे भी तीन गुना अधिक होती है।

पौष्टिक आहार के साथ उज्ज्वल भविष्य भी सौंपेंगी

झाबुआ जिले में 106, अलीराजपुर में 87 और बड़वानी जिले में 117 महिला जनजातीय हितग्राहियों ने प्रथम चरण में कड़कनाथ पालन शुरू कर दिया है। इन जिलों में हितग्राहियों को कुक्कुट विकास निगम द्वारा 10म17 का शेड, बर्तन, 6 माह तक का दाना, वैक्सीनेटेड 50 चूजे दिये जा चुके हैं। झाबुआ में दूसरा चरण आरंभ हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योजना के क्रियान्वयन की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही ये जनजातीय महिलाएं न केवल कड़कनाथ से अच्छी आय का सिलसिला आरंभ करेंगी, बल्कि अपने बच्चों को पौष्टिक आहार के साथ उज्ज्वल भविष्य भी सौंपेंगी।

कड़कनाथ के लिए सब्सिडी और राजस्व

कड़कनाथ कुक्कुट पालन के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन योजना शुरू की है, जो कुक्कुट परियोजना के तहत 25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, इच्छुक व्यक्ति बैंक ऋण, नाबार्ड ऋण और कई अन्य वित्तीय संस्थानों से भी सस्ती दरों पर ऋण प्राप्त करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक कड़कनाथ मुर्गी पालन कर सालाना 35 लाख रुपये तक कमा सकते हैं। कड़कनाथ कुक्कुट पालन योजना का लाभ सतना जिले के उचेहरा विकासखंड के कई गांव की महिलाओं ने उठाया है। जानकारी के मुताबिक, जनजातीय बाहुल्य ग्राम गोबरांव कला, पिथौराबाद, धनेह, जिगनहट, बांधी, मौहार और नरहटी में जनजातीय महिलाओं के लिए करीब 30 कड़कनाथ कुक्कुट इकाइयां स्थापित की गई हैं। इन्हें पहले चरण में 40-40 कड़कनाथ चूजे और उच्च गुणवत्ता से परिपूर्ण 58 किलोग्राम कुक्कुट आहार दिया गया है। हितग्राही रूमी कोल कहती हैं कि यह योजना ने हमारी खुशहाली लेकर आयी है। हमारे घर-परिवार को पौष्टिक आहार तो मिलेगा ही, हमारी आमदनी भी कई गुना बढ़ जायेगी।

दो दिन के मप्र दौरे पर आईं कृषि विकास विभाग भारत सरकार की संयुक्त सचिव डॉ. विजया लक्ष्मी नदेंडला

संयुक्त सचिव कृषि ने किया ई-नाम योजना की समीक्षा

भोपाल। जागत गांव हमार

किसान तथा कृषि विकास विभाग भारत सरकार नई दिल्ली की संयुक्त सचिव डॉ. विजया लक्ष्मी नदेंडला द्वारा दो दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे के दौरान प्रथम दिवस मंडी बोर्ड के सभागार में ई-नाम योजना की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में ई-नाम योजना को और सशक्त करने के संबंध में संयुक्त सचिव द्वारा महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिए गए। जिसमें मुख्य रूप से दो राज्यों के मध्य व्यापार को बढ़ावा देने की दृष्टि से लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाना, कृषि जिंसों की गुणवत्ता परीक्षण हेतु उन्नत प्रयोगशालाओ की स्थापना करना, कृषकों को अधिक से अधिक अपनी उपज ई-नाम पोर्टल पर विक्रय करने हेतु प्रोत्साहित करना जिससे कृषकों को उनकी उपज का प्रतिस्पर्धात्मक रूप से अधिक मूल्य प्राप्त हो सके। संयुक्त सचिव द्वारा कृषि विपणन के क्षेत्र में मंडी बोर्ड द्वारा किये जा रहे नवाचारों की प्रसंशा की गई। जिसमें मुख्य रूप से ई-अनुज्ञा पोर्टल, एम.पी. फार्मगेट एप, ई-मंडी पायलेट आदि प्रमुख योजनाएं हैं।

बैठक में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की प्रबंध संचालक जी.व्ही. रश्मि, अपर संचालक डी. के. नागेंद्र, चंद्रशेखर वशिष्ठ, संयुक्त संचालक संगीता ढोके, डी.एम.आई. भोपाल के क्षेत्रीय निदेशक प्रसाद चक्रवर्ती, अधीक्षण यंत्री डी. एस. राठौर, संदीप चौबे सहित विभिन्न मंडियों से आए हुए मंडी सचिव तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

कृषक, व्यापारी और कलाकार हो रहे उपेक्षा का शिकार

बालाघाट बांस को प्लेटफार्म की तलाश, खुलेंगे रोजगार के द्वार

रफी अहमद अंसारी, बालाघाट। जागत गांव हमार

मप्र का बालाघाट जिला गौण खनिज, मैगनीज, तांबा और धान उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी है, लेकिन यहां किसानो द्वारा प्रचुर मात्रा में बांस का भी उत्पादन किया जाता था, जहां बांस की महत्ता का समझने के लिये जिले में एक प्लेटफार्म की आवश्यक्ता है। जिसको लेकर बांस उत्पादन करने वाले किसानों, व्यापारियो और बांस शिल्प कलाकारों के साथ विचार मंथन करना होगा और बांस आधारित उद्योगों की नींव रखी जानी चाहिये। ताकि जिले में बांस उत्पादक किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारो को एक बेहतर प्लेटफार्म मिल सके।

बालाघाट जिले में बांस आधारित विकास की संभावनाओं को भांपने प्रयास किया गया, तो निश्चित ही सफलता हाथ लगेगी। क्योकि यहां बांस का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता था, जब मप्र के खंडवा जिले के नेपानगर और महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के

चंगेरा में पेपर मिल हुआ करती थी। लेकिन कालांतर में सबकुछ सिमटकर रह गया। बांस उत्पादक किसानों की माने तो उनके पास बांस तो है, लेकिन कोई खरीददार नहीं मिलता। वही व्यापारियों को परिवहन के लिए टी.पी. की आवश्यकता पड़ती है। यदि बांस निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिये काम किया जाये तो उत्पादों के डिजाइन और क्वालिटी में सुधार के लिए काम करने वाले कलाकारों को ट्रेनिंग की निहायत आवश्यकता भी होगी।

जागरूकता के अभाव में सिमट रहा उत्पादन- वैसे बालाघाट जिले में बांस, मेनपावर, मशीनें, मार्केट तो उपलब्ध हैं, लेकिन सबको समेटकर एक प्लेटफार्म पर लाने की आवश्यक्ता है। जिले के नक्सल क्षेत्रो से बांस आधारित उत्पाद बनाने वाले कारीगरो की कोई कमी नहीं है, जिनके बेहतर विकास के लिये उन्हे बेहतर ट्रेनिंग देने की आवश्यक्ता है। देखा जाये तो बांस खरीदार को नहीं मालूम कि अब बांस कहां मिलेगा, वहीं किसानों को नहीं मालूम कि उनका बांस कौन खरीदेगा, इसी उलझन में बांस का उत्पादन धीरे धीरे सिमटते जा रहा है।

तो उत्पादन के साथ बढ़ सकता है रोजगार

वर्तमान में बांस से सूपा, टुकना, बांसुरी,फर्नीचर इत्यादी उत्पाद बनाये जा रहे हैं, जिनकी मानव जीवन में आवश्यक्ता बढ़ती जा रही है। वही जिले में अब अगरबत्ती का भी कारोबार प्रगति पर है। लेकिन इसके लिये बम्बुकूसा स्टीक व कोलडा से बनने वाली काडी चाईना और वेदनाम से आयात की जाती है। जो भारत को 100 रूपये प्रति किलो प्राप्त होती है। लेकिन इसके उत्पादन की बात करे क्षमता सिर्फ 20 प्रतिशत ही रह गई है। जहां यह माना जा सकता है कि अगरबत्ती निर्माण के लिये काड़ी की खपत ज्यादा है और उत्पादन बेहद कम। ऐसे में उद्योग मीट के माध्यम से बांस आधारित उद्योग स्थापित करने की नितांत आवश्यक्ता है। यदि बांस आधारित उद्योग स्थापित हुए तो निश्चित ही सिवनी, छिंदवाडा और बालाघाट जिले में एक बार पुनः बांस का उत्पादन बढ़ जायेगा और किसानो को अच्छा रोजगार भी मिलेगा।

लोक सेवा गारंटी योजना में राजस्व विभाग की एक और सेवा हुई शामिल

अब एक दिन में जारी होगा भूमि का नो-ड्यूज प्रमाण पत्रः गोविंद सिंह राजपूत

भोपाल। जागत गांव हमार

अभिनव प्रयोगों और नवाचारों के जरिये राजस्व के पुराने कई नियमों में बदलाव कर आम जनमानस को बड़ी राहत पहुंचाने में जुटे प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने प्रदेश के किसानों के हित में एक और महत्ववपूर्ण निर्णय लिया है।

अब नो-ड्यूज प्रमाण ऑनलाइन

इस निर्णय के अनुसार किसानों की भूमि पर लगने वाले भू-राजस्व एवं अन्य उपकर, बैंक बंधक एवं जमानत संबंधी जो भी जानकारी खसरे/खतोनी में दर्ज होगी, उसके आधार पर आम जनता के सुविधा के लिये अब नो-ड्यूज प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी करने की नई व्यवस्था लागू की जा रही है।

तहसील का चक्कर से मुक्ति

इस बदलाव की जानकारी देते हुए प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया की पहले भूमि के नो-ड्यूज प्रमाण पत्र के लिये किसानों को तहसील कार्यालय में जाकर आवेदन करना पड़ता था एवं नो-ड्यूज प्रमाण पत्र के लिए तहसील के चक्कर लगाना पड़ता था। इससे किसानों को परेशान होना पड़ता था साथ ही साथ समय और धन की बर्बादी होती थी।

श्री राजपूत ने बताया कि नो-ड्यूज प्रमाण पत्र जारी करने के सिस्टम में बदलाव कर इस सेवा को लोक सेवा गारंटी योजना में शामिल करने से किसानों एवं आम जनता को एक दिवस में भूमि का नो-ड्यूज प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा अनिवार्य रूप से जारी करना होगा।

नोडयूज न मिलने पर अपील की व्यवस्था

यदि तहसीलदार द्वारा नियत अवधि एक कार्य दिवस में भूमि का नो-ड्यूज प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है तो इसकी प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी एवं द्वितीय अपील संबंधित जिला कलेक्टर को करनी होगी। इसके बाद उन्हें नो-ड्यूज प्रमाण प्राप्त हो सकेगा।

पहले भी हो चुके हैं कई बदलाव

किसानों को लगने वाले नो-ड्यूज प्रमाण पत्र को लोक सेवा गारंटी में शामिल करने से पहले भी राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत प्रदेश के किसानों और आम जनता की सुविधा के लिए ऐसे कई नियमों में बदलाव कर सुविधाजनक बनाया है, जिनमें इन 70 सालों में कोई बदलाव नहीं हुआ। ऑनलाइन खसरा-खतौनी, भू-अधिकार पुस्तिका, ऑनलाइन नामान्तरण तथा सायबर तहसील की स्थापना जैसे कई महत्वपूर्ण नवाचार हैं, जो प्रक्रिया को सरल बनाते हैं।

वर्ष भर में 40 प्रकरण बनाकर 5 गुना मण्डी शुल्क वसूला, मण्डी शुल्क वसूली पर भी लगाई रोक

कृषि उपज मण्डी प्रबंधन के प्रयासों से 117 प्रतिशत राजस्व आय में की वृद्धि

खेमराज मौर्य, शिवपुरी। जागत गांव हमार

किसानों के लिए कृषक हित में संचालित कृषि उपज मण्डी समिति ग्राम पिपरसमां के द्वारा शासन के निर्देशों और कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह एवं भार साधक अधिकारी (एसडीएम)गणेश जायसवाल के मार्गदर्शन में मण्डी सचिव हरेन्द्र सिंह राठौड़ की कुशल रणनीति के तहत एक वर्ष में ही मण्डी के राजस्व आय में मण्डी प्रबंधन के प्रयासों से 117 प्रतिशत राजस्व आय की वृद्धि की गई है। इसके अलावा मण्डी सचिव हरेन्द्र सिंह राठौड़ की पदस्थापना के बाद से लेकर अब तक पूर्व कर्मचारियों का शेष बकाया वेतन सहित मण्डी शुल्क वसूली पर भी रोक लगाने का कार्य किया गया और विगत वर्ष की तुलना में आय रूपये 15427318 की अपेक्षा इस वर्ष आय रूपये 33531554 की वसूली कर 117 प्रतिशत राजस्व आय में वृद्धि की गई। साथ ही कर्मचारियों का रूका हुआ दो माह का वेतन एवं 40 प्रकरण बनाए जाकर पांच गुना मण्डी शुल्क के रूप में 10620265 वसूल की गई। मण्डी सचिव हरेन्द्र राठौड़ ने बताया कि मण्डी शुल्क की वसूली में कोई चोरी नहीं की हो रही है साथ अवैध वसूली पर भी रोक लगाने में मण्डी प्रबंधन कामयाब रहा है। इस दौरान वर्ष भर में मण्डी राजस्य आय एवं कर्मचारियों के वेतन सहित विभिन्न प्रकरण बनाकर वसूली करने के मामले में संयुक्त संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ग्वालियर के द्वारा शिवपुरी कृषि उपज मण्डी निरीक्षण के दौरान आय-आवक वृद्धि का प्रशंसा पत्र भी प्रदान किया गया।

इस तरह हुई राजस्व आय में वृद्धि, बनाए 40 प्रकरण, 5 गुना वसूला मंडी शुल्क

मण्डी सचिव हरेन्द्र सिंह राठौड़ के अनुसार राजस्व आय वृद्धि को लेकर की गई कार्यवाही के संबंध में बताया कि जिसमें पांच प्रकरण बनाए गए है इसमें नवम्बर 2021 में कुल 14 प्रकरण बनाए और मण्डी शुल्क 294933, समझौता शुल्क 21500, निराश्रित शुल्क 7488, 255 क्विंटल आवक हुई, इसके साथ ही दिसम्बर में 5 प्रकरण बनाए जिसमें मण्डी शुल्क 250213, समझौता शुल्क 14000, निराश्रित शुल्क 6672, 693 क्विंटल आवक हुई, जनवरी 2022 में 7 प्रकरण बनाए जिसमें मंडी शुल्क 246870, समझौता शुल्क 15500, निराश्रित शुल्क 3883, 586 क्विंटल आवक हुई, फरवरी 2022 में 4 प्रकरण बनाए जाकर मंडी शुल्क 17422, समझौता शुल्क 2500, निराश्रित शुल्क 465, 74.80 क्विंटल आवक हुई, मार्च में 4 प्रकरण बनाए मंडी शुल्क 228766, समझौता शुल्क 9000, निराश्रित शुल्क 6130, 672 क्विंटल आवक हुई। इस तरह कुल 34 प्रकरण बनाए जाकर मंडी शुल्क 1038204, समझौता शुल्क 62500, निराश्रित शुल्क 24638 और 2206 क्विंटल आवक में यह कार्यवाही की गई। इसके साथ ही पांच गुना प्रकरण बनाए जाने को लेकर मई 2022 में 2 प्रकरण बनाए मंडी शुल्क 111530, समझौता शुल्क 9000, निराश्रित शुल्क 2974, 508 क्विंटल आवक में, अगस्त 2022 में 1 प्रकरण बनाया जाकर मंडी शुल्क 52229, समझौता शुल्क 5000, निराश्रित शुल्क 1393, 309 आवक क्विंटल में वसूली की गई। इस तरह कुल 3 प्रकरण पांच गुना बनाया जाकर मंडी शुल्क में 163759, समझौता शुल्क 14000, निराश्रित शुल्क 4367, कुल 817 क्विंटल आवक में वसूली की गई।

किसानों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी

बिजली न होने से पिछड़ी क्षेत्र में बोवनी, सिर्फ 20प्रतिशत ही हो पाई

पिछोर। जागत गांव हमार

पिछोर अनुविभाग के 12 से अधिक गांवों में बिजली सप्लाई ठप होने के कारण किसानों की रबी की फसल की बोवनी नहीं हो पा रही है। स्थिति यह है कि किसानों को 24 घंटे में बमुश्किल 2 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। जिस वजह से अभी क्षेत्र के किसानों की 20 फीसदी बोहनी ही हो सकी है। बिजली ना होने से खेतों में सिंचाई के अभाव में किसान बोवनी नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि अब किसानों ने आंदोलन का मन बनाते हुए चेतावनी दी है अगर उनकी समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो वह उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार होंगे। अंचल के पिछोर क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक ग्रामों में बिजली सप्लाई ना हो पाने के कारण किसान खेती ना करने के लिए मजबूर हैं। बिजली समस्या से परेशान किसान नारायण दाऊ, दीनदयाल, धर्मेंद्र दुबे, कल्ला कारपेंटर, मनीराम, रामजी दुबे हिम्मतपुर, नीरज मिश्रा, सुरेंद्र सुजावनी आदि का कहना है कि 24 घंटों में सिर्फ 10 मिनट के लिए टुकड़ों में दिन में लगभग एक-डेढ़ घंटे ही बिजली मिल पा रही है। किसानों का यह भी कहना है कि अनुभाग की 4 ग्राम पंचायतों के लगभग 15 बड़े गांवों में बिजली ना मिल पाने से किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। जहां सिंचाई के अभाव में अब तक किसानों की बोवनी नहीं हो सकी है। ऐसे में अब यह तय है कि इस साल क्षेत्र में खेती का रकबा घट जाएगा।

कुछ दिन पहले तो थोड़ी बहुत बीच-बीच में इस तरह की समस्या थी, लेकिन अब ऐसा कहीं नहीं है। यदि ऐसा है तो हम दुरुस्त करा रहे हैं। फिर भी मुझे ग्रामीणों ने कोई सूचना नहीं दी है।
दीपांकर गौतम,डीई बिजली कंपनी पिछोर

जिन ग्रामों में विद्युत सप्लाई नहीं हो पा रही है, इस संबंध में विद्युत विभाग से बात करता हूं। किसानों की समस्या का शीघ्र समाधान किया जाएगा।
-विजेंद्र सिंह यादव, एसडीएम पिछोर

खेतों में पशुओं को भगाने में आएगी काम, राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में होगा मॉडल का प्रदर्शन

रतलाम के छात्र ने बनाई गन, किसानों के लिए साबित होगी मददगार

अमित निगम, रतलाम। जागत गांव हमार

जिले से आए कक्षा दसवीं के गोयम जैन ने किसानों के लिए उपयोग के लिए एक गन तैयार की है, जिसकी मदद से किसान खेत में आने वाले पशुओं को दूर से ही भगा सकते हैं। गोयम जैन का यह माडल राज्य स्तरीय प्रदर्शन के लिए चयनित हुआ है। गोयम ने बताया कि किसानों के लिए बंदूक बनाई है, जो उनके लिए बहुत उपयोगी है। इसमें कैल्शियम कार्बाइड डलेगा। दस ग्राम कैल्शियम कार्बाइड के अंदर थोड़ा-सा पानी डालेंगे तो दोनों के मिश्रण से एक गैस का निर्माण होगा। गन के निचले हिस्से में एक गैस चूल्हे वाला लाइटर लगा है, जिसे दबाने पर स्पार्क होगा और गैस में आग लगने से जोर से आवाज

आएगी। यह तेज आवाज होती है, जिसकी मदद से खेत में आने वाले जानवरों को किसान दूर से ही भगा सकते हैं। रात के समय में भी यह बहुत उपयोगी है। नील गाय व अन्य जानवर कई बार खेत में लगी फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं। गन को बनाने की लागत 100 से 200 रुपए की बीच है। पीवीसी पाईप की मदद से गन को तैयार किया जाता है। छात्रा नंदिनी खांडे ने चप्पल में ऐसा डिवाइस लगाया। जिससे चप्पल पहनकर चलने पर पावर बैंक चार्ज हो जाता है। इसकी मदद से मोबाइल फोन चार्ज किया जाता है। वहीं स्टूडेंट रितेश आंजना ने ऐसा डिवाइस तैयार किया है, जो दृष्टिहीन को सड़क पर चलने में मदद करता है। जूते के सोल में एक डिवाइस लगाया है, जो स्पीड ब्रेकर, पत्थर व अन्य वस्तुएं सामने आने पर सायरन बजाता है। इससे दृष्टिहीन व्यक्ति अलर्ट हो जाता है। प्रदर्शनी में बर्तन धोने की मशीन, सोलर स्ट्रीट लाइट सहित कई मॉडल शामिल थे।

8 जिलों के स्टूडेंट ने लिया हिस्सा

दरसअल, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 2021-22 की जिला स्तरीय प्रदर्शनी में स्टूडेंट ने अपने मॉडल का प्रदर्शन किया। शासकीय मालव कन्या स्कूल मोती तबेला में स्कूल शिक्षा विभाग ने दो दिवसीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी लगाई, जिसमें स्कूली बच्चों द्वारा बनाए मॉडल को रखा गया। करीब 8 जिलों के 149 स्टूडेंट इसमें शामिल हुए। बुधवार को प्रदर्शनी का अंतिम दिन था। कुल 17 स्टूडेंट के मॉडल का चयन राज्य स्तरीय प्रदर्शनी के लिए किया गया है।

पौधों की वृद्धि और पौधों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक

कृषि के लिए अमृत है पंचगव्य, जानिए लाभ और तैयार करने की विधि

भोपाल। जागत गांव हमार

पंचगव्य एक जैविक उत्पाद है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह पांच मुख्य सामग्री गाय के गोबर, गोमूत्र, गाय के दूध, देसी गाय के घी और दही का उपयोग करके तैयार किया जाता है। पंचगव्य का उपयोग जैविक खेती के लिए किया जाता है क्योंकि यह पौधों की वृद्धि और पौधों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी प्रमुख भूमिका निभाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर पौधे कीटों और उनसे होने वाली बीमारियों से लड़ने में सक्षम होंगे। पंचगव्य की विशेषता इसकी पोषक तत्व सामग्री है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं जो पौधों की वृद्धि और उनके स्वस्थ विकास में सहायक होते हैं। इसमें कई विटामिन, अमीनो एसिड, गिबरेलिन और ऑक्सिन होते हैं जो पौधों के विकास को नियंत्रित करते हैं। इसमें स्यूडोमोनास, एजोटोबैक्टर, फॉस्फोर बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्मजीव भी होते हैं जो पौधों के लिए फायदेमंद माने जाते हैं।

ताजा गाय का गोबर

गोमूत्र	5 लीटर
गाय का दूध	1 लीटर
गाय का दही	1 लीटर
गाय का घी	500 ग्राम
नारियल पानी	1.5 लीटर
गन्ने का रस	1.5 लीटर
पका हुआ केला	6
खमीर	50 ग्राम

पंचगव्य तैयारी की युक्तियां

» अंतिम मिश्रण को एक मिट्टी के बर्तन में जोड़ा जा सकता है जिसमें एक विस्तृत मुंह, एक कंक्रीट या प्लास्टिक की टंकी होती है।
» मिश्रण के साथ कंटेनर खुला रखा जाना चाहिए और आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कंटेनर छाया में है।
» मिश्रण को दिन में दो बार हिलाना सुनिश्चित करें।
» किसान को तैयार मिश्रण को छाया में रखना पसंद करना चाहिए और इसे तार या प्लास्टिक की जाली से ढक देना चाहिए। ऐसा घर की मक्खियों जैसे छोटे कीड़ों को अंडे देने से रोकने और मिश्रण में कीड़ों को बनाने के लिए किया जाना चाहिए।
» भैंस के कोई उत्पाद मिश्रित तो नहीं हैं, इसकी जांच के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए।
» अगर आपके पास गन्ने का रस उपलब्ध नहीं है तो आप 250 ग्राम गुड़ को 1.5 लीटर पानी में मिलाकर गन्ने के रस की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं।

पंचगव्य तैयारी के चरण

पहला स्टेप: सबसे पहले आपको 5 किलो गोबर और 500 ग्राम गाय के घी को मिलाकर एक मिट्टी के बर्तन में डालना है। इस मिश्रण को 3 दिन तक स्टोर करना चाहिए। इन 3 दिनों में इस मिश्रण को दिन में दो बार हिलाना जरूरी है।

दूसरा स्टेप: फिर आपको 5 लीटर गोमूत्र और 5 लीटर पानी लेकर उन्हें पिछले मिश्रण में मिलाना है। इस नए मिश्रण को दो सप्ताह तक स्टोर करना चाहिए। इस मिश्रण को दिन में दो बार हिलाना चाहिए। इस मिश्रण को एक बार सुबह और दूसरी बार शाम को चलाना बेहतर होता है।

तीसरा स्टेप: दो सप्ताह पूरे होने के बाद, आपको 1 लीटर गाय का दूध, 1 लीटर दही, 1.5 लीटर नारियल पानी, 1.5 किलो गुड़, 6 पके केले जोड़ने की जरूरत है। सुनिश्चित करें कि आप पके केले का पेस्ट बना रहे हैं। इस मिश्रण को दिन में तीन बार लगातार चलाते हुए एक महीने तक रखा जाए तो पंचगव्य बनकर तैयार हो जाता है।

विभिन्न व्यावसायिक फसलों पर पंचगव्य के प्रयोग की समय सारिणी

» चावल के लिए, आपको रोपाई के 10, 15, 30 और 50 दिनों के बाद पंचगव्य लगाना होगा।
» सूरजमुखी के लिए बीज बोने के बाद पंचगव्य का प्रयोग करना चाहिए। पंचगव्य को 30, 45 और 60वें दिन लगाएं।
» काले चने के लिए दो शर्तें होंगी। जिस मिट्टी में काले चने उगाए जाते हैं वह वर्षा पर आधारित हो तो फूल आने के पहले दिन पंचगव्य लगाएं। अगला प्रयोग फूल आने के 15 दिन बाद करना चाहिए। यदि मिट्टी सिंचित हो तो बुवाई के बाद पंचगव्य का प्रयोग करना चाहिए। इसे 15वें, 25वें और 40वें दिन लगाया जा सकता है।
» हरे चने की खेती में बुवाई के बाद पंचगव्य का प्रयोग करना चाहिए। बुवाई हो जाने के बाद आप इसे 15वें, 25वें, 30वें, 40वें और 50वें दिन लगा सकते हैं।
» अरंडी उगाते समय बीज बोने के बाद पंचगव्य का प्रयोग करना चाहिए। बुवाई के बाद, इसे 30 और 45 वें दिन लगाया जा सकता है।
» मूंगफली की खेती करते समय बीज बोने के बाद पंचगव्य का प्रयोग करना चाहिए। बुवाई के बाद इसे 25 और 30वें दिन लगाना चाहिए।
» भिंडी की खेती में बीज बोने के बाद पंचगव्य का प्रयोग करना चाहिए। बुवाई के बाद इसे 30, 45, 60 और 75वें दिन लगाना चाहिए।
» टमाटर की खेती में नर्सरी अवस्था के बाद इसे रोपाई के 45वें दिन से लगाना चाहिए। बीज को पंचगव्य के 30 मिलीलीटर घोल में लगभग आधे दिन तक भिगोकर रखना चाहिए।
» प्याज की खेती में रोपाई के बाद पंचगव्य का प्रयोग करना चाहिए। जैसे ही प्रत्यारोपण किया जाता है, इसे जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। इसके बाद 45 और 60वें दिन इसे लगाना चाहिए।
» गुलाब की खेती के लिए पंचगव्य का प्रयोग छंटाई और नवोदित के समय करना चाहिए।
» चमेली की खेती में कलियों के निकलने और जमने के समय पंचगव्य का प्रयोग करना चाहिए।

फसल की बेहतर कीमत मिलने का असर

गेहूं और तिलहन बुवाई के रकबे में 10 फीसदी की बढ़त दर्ज

नई दिल्ली। जागत गांव हमार

विदेशी संकेतों की वजह से इस साल गेहूं और तिलहन फसल के बेहतर भाव मिलने का असर किसानों के द्वारा नए फसल की बुवाई पर भी देखने को मिल रहा है. चालू रबी मौसम में गेहूं और तिलहन फसलों की बुवाई का रकबा सालाना आधार पर 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है। शुक्रवार को जारी कृषि मंत्रालय के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है. इससे ये भी उम्मीद बंधी है कि अगले साल बेहतर उपज से घरेलू बाजार में भाव नियंत्रित रहेंगे. जारी हुए आंकड़ों के अनुसार रबी सत्र में 25 नवंबर तक गेहूं की बुवाई का रकबा 10.50 प्रतिशत बढ़कर 152.88 लाख हेक्टेयर हो गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 138.35 लाख हेक्टेयर था. तिलहन का रकबा 25 नवंबर तक 13.58 प्रतिशत बढ़कर 75.77 लाख हेक्टेयर हो गया है।

मुख्य रबी फसल गेहूं की बुवाई अक्टूबर में शुरू होती है और कटाई मार्च-अप्रैल में शुरू होती है. गेहूं के अलावा, चना और सरसों 2022-23 फसल वर्ष (जुलाई-जून) के रबी मौसम के दौरान उगाई जाने वाली अन्य प्रमुख फसलें हैं।

दालों की बुवाई के रकबे में गिरावट

वहीं दालों के मामले में बुवाई का रकबे में कुछ कमी देखने को मिल रही है। हालांकि ये गिरावट भी सीमित रही है। इस अवधि के दौरान पहले के 94.37 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस बार 94.26 लाख हेक्टेयर पर दलहन बुवाई की गई है। वहीं मोटे अनाज की बुवाई में भी सीमित गिरावट दर्ज हुई है। इस अवधि में मोटे अनाज की बुवाई 26.54 लाख हेक्टेयर में की गई, जो पहले 26.70 लाख हेक्टेयर में की गई थी।

चावल की बुवाई में बढ़त: जबकि इस सीजन में चावल की बुवाई में बढ़त देखने को मिली है और बुवाई का क्षेत्र 9.14 लाख हेक्टेयर में पहुंच गया जबकि पिछले साल की समान अवधि में 8.33 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई थी। इस रबी सत्र में 25 नवंबर को सभी रबी फसलों के तहत कुल खेती का रकबा 7.21 प्रतिशत बढ़कर 358.59 लाख हेक्टेयर हो गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 334.46 लाख हेक्टेयर था।

क्या है आंकड़ों के संकेत

नए आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश (6.40 लाख हेक्टेयर), राजस्थान (5.67 लाख हेक्टेयर), पंजाब (1.55 लाख हेक्टेयर), बिहार (1.05 लाख हेक्टेयर), गुजरात (0.78 लाख हेक्टेयर), जम्मू और कश्मीर (0.74 लाख हेक्टेयर), और उत्तर प्रदेश (0.70 लाख हेक्टेयर) में गेहूं बुवाई के रकबे में बढ़ोतरी हुई है. इस रबी सत्र में 25 नवंबर तक तिलहन का रकबा 13.58 प्रतिशत बढ़कर 75.77 लाख हेक्टेयर हो गया, जबकि एक साल पहले की अवधि में यह रकबा 66.71 लाख हेक्टेयर था. इसमें से इस अवधि के दौरान पहले के 61.96 लाख हेक्टेयर के मुकाबले सरसों की बुवाई 70.89 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है।

बैंक ऑफबड़ौदा के ऐप से किसानों को बैंकिंग से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी मिलेगी

किसानों के लिए खास ऐप 'बॉब वर्ल्ड किसान', मिनटों हल होंगी समस्याएं

नई दिल्ली। जागत गांव हमार

किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी परेशानी कम करने के लिए देश में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में देश के अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने गुरुवार को 'बॉब वर्ल्ड किसान' ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से किसानों को बैंकिंग से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी मिलगी। दरअसल, 'बॉब वर्ल्ड किसान' ऐप एक ऐसा मंच है जो किसानों को फाइनेंसिंग, बीमा और निवेश से संबंधित जानकारी देता है। साथ ही समय के साथ कृषि क्षेत्र को आर्थिक रूप से डिजिटल बनाने में भी मदद करता है। खास बात यह है कि इस ऐप के माध्म से किसान घर बैठे- बैठे ही मंडी भाव मालूम कर सकते हैं। साथ ही इस ऐप के द्वारा किसानों को मौसम से

संबंधित जानकारी भी मिलेगी। वहीं, अगर किसान चाहें तो 'बॉब वर्ल्ड किसान' ऐप के माध्यम से कृषि विशेषज्ञों से सलाह भी ले सकते हैं। जानकारों का कहना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का यह कदम किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। किसानों को अब फॅसलों में लगने वाले रोग से बचाव करने के लिए सरकारी ऑफिसों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वे इस ऐप के द्वारा ही इसका समाधान ढूंढ लेंगे।

तीन भषाओं में है उपलब्ध: रिपोर्ट के मुताबिक, इस ऐप के माध्यम से किसान खेती करने के लिए उपकरणों को भी किराए पर ले सकते हैं। साथ ही उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई- नई तकनीकों के उपयोग के बारे में जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। इससे किसानों को विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक ने एग्रीबेग्री, एग्रोस्टार, बिगहाट, पूर्ति, ईएम3 और स्काईमेट जैसी छह कृषि कंपनियों के साथ साझेदारी भी की है। फ्लिहाल, यह ऐप तीन भाषाओं यानी अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में उपलब्ध है।

आय बढ़ाने में मदद मिलेगी

बैंक ऑफबड़ौदा के कार्यकारी निदेशक जॉयदीप दत्ता रॉय ने कहा कि देश के अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक के रूप में, भारतीय कृषि समुदाय के साथ हमारा गहरा और स्थायी संबंध है। बैंक ऑफबड़ौदा का उदेश्य भारतीय किसानों को उनकी बोने से बेचने की यात्रा के माध्यम से समर्थन देना है। बॉब वर्ल्ड किसान एक अत्याधुनिक और सर्व-समावेशी मंच है जो हमारे अन्नदाताओं को कई तरह की सेवाएं प्रदान करेगा, जिससे उन्हें अपनी उपज और आय को अधिकतम करने में मदद मिलेगी।

पूरे अनुभव को डिजिटाइज़ करता है

बैंक ऑफबड़ौदा के मुख्य डिजिटल अधिकारी अखिल हांडा ने कहा कि पिछले साल लॉन्च किए गए बॉब वर्ल्ड मोबाइल बैंकिंग ऐप ने हमारे लाखों ग्राहकों के लिए बैंकिंग अनुभव को बदल दिया। बॉब वर्ल्ड किसान ऐप के लॉन्च के साथ ही हमारा वादा है कि हम अपने किसानों के लिए भी ऐसा ही करेंगे।

दिल्ली में उच्चायुक्तों और राजदूतों के बीच, अंतरराष्ट्रीय पोषक-अनाज वर्ष का प्री-लांचिंग उत्सव

मिलेट्स का उत्पादन व खपत बढ़ाने के लिए मिशन मोड में काम:कृषि मंत्री

नई दिल्ली। जागत गांव हमार

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तथा विदेश मंत्री डा. एस. जयशंकर की अध्यक्षता में गत दिवस दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में उच्चायुक्तों और राजदूतों के बीच, अंतरराष्ट्रीय पोषक-अनाज वर्ष का प्री-लांचिंग उत्सव हुआ। इस अवसर पर तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय पोषक-अनाज वर्ष (आईवाईओएम) घोषित किया है। इसके माध्यम से मिलेट की घरेलू व वैश्विक खपत बढ़ाना हमारा उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि यह वर्ष वैश्विक उत्पादन बढ़ाने, कुशल प्रसंस्करण तथा फसल रोटेशन के बेहतर उपयोग एवं फूड बास्केट के प्रमुख घटक के रूप में मिलेट को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करेगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय अन्य केंद्रीय मंत्रालयों, सभी राज्य सरकारों एवं अन्य हितधारक संस्थानों के साथ मिलकर मिलेट्स का उत्पादन तथा खपत बढ़ाने के लिए मिशन मोड में काम कर रहा है।

मिलेट्स सूक्ष्म पोषक तत्वों, विटामिन व खनिजों का भंडार

केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि मिलेट्स सूक्ष्म पोषक तत्वों, विटामिन व खनिजों का भंडार है। आईवाईओएम, खाद्य सुरक्षा व पोषण के लिए मिलेट्स के योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा व सतत उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार के लिए हितधारकों को प्रेरित करेगा एवं अनुसंधान तथा विकास सेवाओं में निवेश बढ़ाने के लिए ध्यान आकर्षित करेगा। शाकाहारी खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग के दौर में मिलेट वैकल्पिक खाद्य प्रणाली प्रदान करता है। मिलेट सुरक्षित वातावरण में भी योगदान देता है।

14 राज्यों के 212 जिलों में कार्यक्रम जारी

उन्होंने बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा स्थायी उत्पादन का समर्थन करने, उच्च खपत के लिए जागरूकता पैदा करने, मंडी व मूल्य श्रृंखला विकसित करने तथा अनुसंधान-विकास गतिविधियों के लिए वित्तपोषण भी किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत, मिलेट के लिए पोषक अनाज घटक 14 राज्यों के 212 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा। साथ ही, राज्यों के जरिये किसानों को अनेक सहायता दी जाती है। सरकार ने अप्रैल-2018 में इसे पोषक-अनाज के रूप में अधिसूचित किया था।

500 से अधिक स्टार्टअप मिलेट मूल्यवर्धित श्रृंखला में काम कर रहे

तोमर ने बताया कि भारत में मिलेट मूल्यवर्धित श्रृंखला में 500 से अधिक स्टार्टअप काम कर रहे हैं, भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान ने आरकेवीवाई-रफ्तार में 250 स्टार्टअप को इनक्यूबेट किया है। 66 से अधिक स्टार्टअप्स को सवा छह करोड़ रु. से ज्यादा दिए गए हैं, वहीं 25 स्टार्टअप्स को भी राशि की की मंजूरी दी है। मिलेट की खपत बढ़ाने वाले व्यंजनों व मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए स्टार्ट-अप-उद्यमियों को भी सहायता दी जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अब खाद्य वितरण कार्यक्रमों का ध्यान आधारभूत कैलोरी से हटाकर अधिक विविध फूड बास्केट प्रदान करने में होना चाहिए, जिसमें प्री-स्कूल के बच्चों व प्रजनन आयु की महिलाओं की पोषण स्थिति में सुधार करने के लिए मिलेट्स शामिल हैं। नीति आयोग व विश्व खाद्य कार्यक्रम का इरादा चुनौतियों को व्यवस्थित- प्रभावी तरीके से पहचानकर समाधान करने का है। यह साझेदारी मिलेट को मुख्यधारा में लाने पर ध्यान केंद्रित करेगी व वर्ष के रूप में मिलेट के लिए अवसरों का उपयोग कर ज्ञान के आदान-प्रदान में विश्व स्तर पर नेतृत्व करने में भारत का समर्थन करेगी।

पोषक-अनाज खाद्य सुरक्षा के साथ अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए भी महत्वपूर्ण

विदेश मंत्री डा. जयशंकर ने कहा कि मिलेट्स आत्मनिर्भरता में सुधार करेगा, विकेंद्रीकृत उत्पादन को बढ़ावा देगा और किसानों की आय में वृद्धि करेगा। इस प्रकार वे वैश्विक खाद्य सुरक्षा के जोखिम को कम करेंगे। भारत की कल्पना के अनुरूप यह वर्ष जागरूकता और उपयोग के मायने में वास्तव में वैश्विक साझेदारी है। उन्होंने कहा कि कोविड, जलवायु परिवर्तन और संघर्षों की पृष्ठभूमि में आज दुनिया में मिलेट्स की प्रासंगिकता बढ़ रही है। जयशंकर ने जोर देकर कहा कि पोषक-अनाज खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोविड एक ऐसा दौर था, जिसने दुनिया को याद दिलाया कि एक महामारी खाद्य सुरक्षा के लिए क्या कर सकती है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से उत्पादन कम हो सकता है और व्यापार बाधित हो सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में खाद्य सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। कार्यक्रम में विदेश राज्य मंत्री मती मीनाक्षी लेखी व कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे भी विशेष रूप से उपस्थित थीं। कृषि सचिव मनोज अहूजा ने स्वागत भाषण दिया व संयुक्त सचिव मती शुभा ठाकुर ने प्रेजेन्टेशन के माध्यम से आईवाईओएम के संबंध में जानकारी दी। अपर सचिव अभिलक्ष लिखी ने आभार माना। यहां विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) डी. रवि, सचिव (पश्चिम) संजय वर्मा व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर लंच में भारतीय मिलेट्स की विविधता व व्यंजनों को प्रदर्शित करने के लिए विस्तृत क्यूरेटेड मिलेट्स बुफे शामिल किया गया। मिलेट्स पाक अनुभव व औपचारिक चर्चा के साथ, मिलेट्स आधारित 30 भारतीय स्टार्टअप्स ने रेडी-टू-ईट व रेडी-टू-कुक मिलेट्स आइटम सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शनी में भाग लिया।

एक गाय पालने पर मिलेंगे 900

खरगोन। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केंद्र खरगोन में गत दिनों जिले के प्राकृतिक व जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह राजपूत, प्रदेश महामंत्री पुरुषोत्तम शर्मा, जिला अध्यक्ष महेश गुर्जर, महामंत्री संतोष चौहान, कृषि वैज्ञानिक एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।

इस कृषक गोष्ठी में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. जी. एस. कुलमी, सह संचालक अनुसंधान डॉ. व्हाय. के. जैन, डॉ. संजीव वर्मा, डॉ. आरके सिंह, डॉ. सुनील त्यागी, विनोद मित्तोलिया, कृषि विभाग से पी. एस. बार्चे ने किसानों को प्राकृतिक एवं जैविक खेती संबंधी जानकारी दी। प्राकृतिक एवं जैविक खेती करने में किसानों के समक्ष आ रही समस्याओं को श्री चौधरी के समक्ष किसानों द्वारा रखा गया, जिसके समाधान के लिए उन्होंने सरकार स्तर पर बात करने की बात कही। डॉ. आरके सिंह ने कृषक जगत को बताया कि इस कृषक संगोष्ठी में 44 किसानों ने सहभागिता की।

भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी ने कार्यक्रम में उपस्थित किसानों से अधिक संख्या में प्राकृतिक खेती को अपनाने का आह्वान किया। श्री चौधरी ने बताया कि शासन द्वारा एक गाय को पालने पर गौपालक को 900 रु प्रति माह दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

वन विभाग में की जाएगी 1772 वन रक्षकों की भर्ती

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों में खाली पड़े अलग-अलग संवर्ग के पदों के भरने के लिए शिवराज सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब रिक्त पदों से 5 फीसदी भर्ती वाले कैप को हटा लिया गया है। इससे अब प्रदेश में तीन चरणों में करीब 70 हजार सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी। यानी युवाओं के लिए सराकारी नौकरी पाने सुनहरा अवसर है। पटवारी भर्ती के बाद अब वन विभाग ने भर्तियां निकाली है।

वन विभाग की भर्ती के लिए अभी आधिकारीक सूचना और डेटशीट जारी नहीं की गई है। माना जा रहा है कि जल्द इस संबंध में विभाग की ओर से कार्रवाई पूरी होने के बाद कर्मचारी चयन मंडल नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। इसके बाद ही तारीख, योग्यता, फीस सेलेबस आदि के बारे में ज्यादा जानकारी मिल सकती है। फिलहाल कर्मचारी चयन मंडल ने एक रूलबुक जारी की है, जिसमें इन भर्तियों को लेकर डिटेल दी गई है।

इन पदों पर होगी भर्ती

- » वन विभाग में कुल 1926 रिक्त पदों पर भर्ती होगी
- » 1772 वनरक्षकों की के पद भरे जाएंगे
- » स्टेनो टाइपिस्ट के 37 पद भरे जाएंगे
- » सहायक ग्रेड-3 के 87 पद भरे जाएंगे
- » मानचित्रकार के 30 पदों पर सीधी भर्ती होगी

जिलेवार अलग-अलग पदों पर होंगी भर्तियां

इस भर्ती में जिन जिलों में पद खाली हैं उन्हें शामिल किया गया है। इसमें से सबसे ज्यादा वनरक्षकों के खाली पदों की संख्या वाले जिलों में बैतूल, सागर, बालाघाट शामिल हैं।

- बैतूल में 191 पद खाली हैं
- सागर में 150 पद खाली हैं
- बालाघाट में 147 पद खाली हैं

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)